

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष - 02

अंक - 238

जौनपुर, शनिवार, 25 मई 2024

सान्ध्य दैनिक (संस्करण)

पेज - 4

मूल्य - 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

श्रावस्ती व सुल्तानपुर सहित 14 सीटों पर मतदान, पोलिंग पार्टियों की रवानगी शुरू

बलरामपुर, संवाददाता। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी शुरू हो गई है। इस चरण में प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर शनिवार को मतदान होगा। श्रावस्ती लोकसभा सीट से जुड़ी तीन विधानसभा क्षेत्र में मतदान करने के लिए शुक्रवार को पोलिंग पार्टियों की रवानगी शुरू हो गई है। सदर, तुलसीपुर व गैसडी विधानसभा क्षेत्रों में 25 मई को 1260 बूथों पर वोटिंग कराई जाएगी। सभी पोलिंग पार्टियों को स्पोर्ट्स स्टेडियम में बस्ता, ईवीएम व वीवीपेट आदि चुनाव सामग्री देने के लिए टेंट की व्यवस्था की गई है। बड़ा परेड में जीपीएस से लैस 780 छोटे-बड़े वाहनों का इंतजाम किया गया है। चुनाव में 5040 और उप चुनाव में 626 कार्मिकों को लगाया गया है। पोलिंग पार्टियों की रवानगी शुरू हो गई है। डीएम अरविंद सिंह व एसपी केशव कुमार ने भ्रमण करके जायजा लिया है। वहीं, भिनागा और श्रावस्ती विधानसभा क्षेत्र के लिए भी कलेक्ट्रेट से पोलिंग पार्टियों की रवानगी शुरू हो गई है। सभी पोलिंग पार्टियों को कलेक्ट्रेट में ईवीएम व वीवीपेट सहित मतदान सामग्री देने की व्यवस्था की गई है।

सुल्तानपुर में वरुण ने दिया भावुक भाषण

सुल्तानपुर, संवाददाता। पीलीभीत से टिकट कटने के बाद भाजपा सांसद वरुण गांधी बृहस्पतिवार को पहली बार चुनाव प्रचार में नजर आए। उन्होंने सुल्तानपुर में ताबड़तोड़ नुककड़ सभाएं कीं, जिसमें वे बार-बार भावुक हुए। कहा कि मैं सिर्फ अपनी मां के लिए सुल्तानपुर में प्रचार करने आया हूँ। यहाँ की मिट्टी से पिता संजय गांधी की खुशबू आती है। अब सुल्तानपुर में मां हैं। मां के नाते अब यह मेरी मातृभूमि भी है। इस बीच उन्होंने न भाजपा का नाम लिया और न ही भाजपा नेताओं का। सुबह सुल्तानपुर पहुंचने पर समर्थकों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने सुल्तानपुर कस्बे की निषाद बस्ती में पहली जनसभा की। यहाँ से वह मोतीगंज, कुछमुछ, बरगदवा महनपुर देवघर, छाप गोलवा,मझगांव,कटघरा चिरान पट्टी, बेरा मारुफपुर, सरैया बाजार, खैरहा, काछा मिटौरा पहुंचे। वरुण गांधी ने कहा कि सुल्तानपुर से उनका पारिवारिक रिश्ता है। वे यहाँ नेता नहीं, एक बेटे के रूप में आए हैं। वरुण ने कहा कि अभी नहीं जबसे हम पैदा हुए तबसे यह हमारी कर्मभूमि है। यह हमारा परिवार है। हमको यहाँ की मिट्टी से प्यार है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार आप लोग सारे रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। मेरा विपक्ष के किसी प्रत्याशी से भी कोई बैर नहीं है।

शांतिपूर्ण हुआ मतदान, जौनपुर लोकसभा में 55.52 प्रतिशत व मछलीशहर में 54.43 प्रतिशत पड़ा वोट



ब्यूरो प्रमुख विश्व प्रकाश श्रीवास्तव जौनपुर। लोकतंत्र के पर्व पर शनिवार को जिले की दो लोकसभा सीटों 73 जौनपुर व 74 मछलीशहर में सुबह 7 बजे से ही सभी मतदान केंद्रों पर वोटों का उत्साह देखने को मिला। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं ने सुबह से अपने कामकाज को जल्दी कर अपने मतदान के प्रति उत्साहित दिखीं। युवा व पहली बार मतदान करने वाले वोटर्स में भी काफी उत्साह देखने को मिला। युवा वोटर्स बोले उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने, राष्ट्रहित



थी। संवेदनशील बूथों पर पैरा मिलिट्री फोर्स लगाया था। समय समय पर व्यवस्था परखने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाई थी। जौनपुर से भाजपा प्रत्यासी कृपा शंकर सिंह ने अपनी पत्नी के साथ सुबह शीतला चौकियां माता का दर्शन किया। उसके बाद सुबह लगभग 8 बजे अपने गांव सहां दर पुर पहुंचकर मतदान किया। उन्होंने भाजपा के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए अपील की। और अपने जीत का दावा किया। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री गिरीश यादव ने अपने परिवार के साथ



अपने गांव में मतदान किया। बसपा प्रत्यासी श्याम सिंह यादव मीडिया से बचते हुए सुबह लगभग 11 बजे मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाई थी। जौनपुर से भाजपा प्रत्यासी कृपा शंकर सिंह ने अपनी पत्नी के साथ सुबह शीतला चौकियां माता का दर्शन किया। उसके बाद सुबह लगभग 8 बजे अपने गांव सहां दर पुर पहुंचकर मतदान किया। उन्होंने भाजपा के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए अपील की। और अपने जीत का दावा किया। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री गिरीश यादव ने अपने परिवार के साथ

के कंट्रोल यूनिट को बदल कर मतदान को शुरू करवाया गया। जिससे लगभग 1 घंटे मतदान देरी से शुरू हुआ। 73 जौनपुर लोकसभा में सुबह नौ बजे तक 13.12, 11 बजे तक 26.84, दोपहर एक बजे तक 37.41, तीन बजे तक 43.63, तथा शाम 5 बजे तक 52.52 प्रतिशत मतदान हुआ। तथा 73 जौनपुर लोकसभा में कुल मत 55.52 और मछलीशहर में 54.43 प्रतिशत कुल मत रहा। वहीं मछलीशहर सुबह सुबह लोकसभा क्षेत्र के बनपुरवा गांव में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। अभी तक इस बूथ पर सुबह सिर्फ

एक मतदान हुआ है। ग्रामीणों ने का कहना है कि पिछले कई सालों से गांव में विकास के नाम पर कोई कार्य नहीं हुआ है। वर्तमान बीजेपी सांसद वीपी सरोज से कई बार गांव के विकास के लिए कहा गया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए आज मतदान का बहिष्कार किया गया है। मौके पर एसडीएम मडियाहूँ कुणाल गौरव के साथ तहसीलदार ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया लेकिन ग्रामीण मनाने को तैयार नहीं हुए। सूचना के बाद सीडीओ साई सीलम तेजा भी गांव में पहुंच गए। काफी प्रयासों के बाद ग्रामीण वोट डालने को तैयार हुए। सीडीओ ने बताया कि समझाने के बाद सभी ग्रामीणों ने वोटिंग किया। प्रशासन के प्रयास से वोटिंग पूरी तरह से हुई है। वहीं मछलीशहर लोकसभा क्षेत्र में मतदान करवाने को लेकर भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज जायसवाल और कार्यकर्ता रूपेश जायसवाल आपस में मिड गए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने

भारत की बढ़ती ताकत वैश्विक संतुलन के लिए जरूरी - विदेश मंत्री जयशंकर

नई दिल्ली, एजेसी। भारत ने एक बार फिर अपनी बढ़ती ताकत का दांव ठोका है और कहा है कि वैश्विक संतुलन कायम करने और खास तौर एशिया को बहुधुवीय बनाने के लिए भारत का मजबूत रहना जरूरी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने निक्की एशिया 2024 (एशिया का भविष्य) सम्मेलन में कहा है कि एशिया को बहुधुवीय बनाने के लिए भारत में बदलाव जरूरी है, क्योंकि बहुधुवीय एशिया से ही बहुधुवीय विश्व का गठन होगा। भारत की बढ़ती ताकत यह सुनिश्चित करेगा कि विश्व में आजादी, खुलापन, पारदर्शिता और

बदलाव हो सकता है। यह देखा जा सकता है कि भारत किस तरह से समाजिक-आर्थिक लाभों का



पेश करने में विश्वास रखता है। भारत में चुनाव चल रहा है जो बताता है कि लोकतंत्र से भी

अगले दोनों चरण के चुनाव में 'इंडिया' गठबंधन उग्र की सभी 27 सीटों जीत रहा है - अखिलेश यादव

लखनऊ, संवाददाता। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को दावा किया कि छठे और सातवें चरण के चुनाव

एक जून को है। अंतिम चरण के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र वाराणसी भी शामिल है। सपा कार्यालय से जारी बयान से भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सफाया होगा। समाजवादी पीडीए परिवार 'इंडिया' गठबंधन के साथ जिस तरीके से मिलकर भाजपा का सफाया कर रहा है, उससे साफ जाहिर है कि छठे और सातवें चरण के चुनाव में इंडिया गठबंधन लोकसभा की 27 की 27 सीटें जीतकर इतिहास रचने जा रहा है। यादव ने कहा, "भाजपा ने जनता से जितने झूठे वादे किए उससे व्यापक आक्रोश है। लोगों को अब भाजपा नेतृत्व के वादों और गारंटी पर तनिक भी विश्वास नहीं हो रहा है। भाजपा ने लोगों को टीका लगाकर उनका जीवन संकट में डाल दिया। खेतीबाड़ी से जुड़े लोग जानते हैं कि 10 साल में किसान सबसे ज्यादा परेशान रहा है। किसान की आय दुगुनी तो हुई नहीं उत्पादन लागत बढ़ा दी गई।



में 'इंडिया' गठबंधन उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सभी 27 सीटें जीतकर इतिहास रचने जा रहा है। छठे चरण का मतदान कल शनिवार को है, जबकि सातवें चरण का मतदान

दुनिया के कई नेता पीएम मोदी को बॉस और महान कहते - राजनाथ सिंह

नई दिल्ली, एजेसी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता था, लेकिन आज जब वह बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है, उन्होंने कहा कि दुनिया के कई नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बॉस कहते हैं और उनका आदर करें। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के ब्रह्मचारी और कुशासन पर परोक्ष हमला बोला। उन्होंने कहा कि सिर्फ 25 साल पहले, भारत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर गंभीरता से नहीं लिया जाता था, लेकिन पीएम मोदी के प्रभावी नेतृत्व के कारण, अन्य देश अब भारत की आवाज पर ध्यान देते हैं। कई वैश्विक नेता प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मान की दृ

ष्टि से देखते हैं, कुछ ने तो यहां तक कहा है उसे बॉस या महान कहें। भारत दुनिया की 5वीं सबसे



बड़ी अर्थव्यवस्था सिंह ने कहा कि 2004 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, लेकिन

सबसे पहले मदद पहुंचाने वालों में होता है। सौर ऊर्जा से लेकर जैवविविधता के मामले में भारत लीडर की भूमिका निभा रहा है। हम यह मानते हैं कि एक मुक्त, खुला, सुरक्षित, शांतिपूर्ण, संपन्न व स्थिर हिंद-प्रशांत क्षेत्र विश्व की शांति व स्थिरता के लिए भी अनिवार्य शर्त है। इस अवसर पर भारतीय विदेश मंत्री ने भारत और जापान के रिश्तों का जिक्र करते हुए इन्हें और ज्यादा प्रगाढ़ करने की जरूरत बताई। जापान की मदद से भारत में चल रहे विकास कार्यों और पूर्वांतर क्षेत्र में चल रहे सहयोग का खास तौर पर जिक्र किया।

अगर सीमाएं सुरक्षित रहतीं तो और तेजी से प्रगति करता भारत - अजित डोभाल

नई दिल्ली, एजेसी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने कहा कि पिछले 10 सालों में देश तेजी से सशक्त हुआ है। हालांकि, अगर हमारे देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित, सुरक्षित और प्रतिकूल कब्जेवाली नहीं होतीं, तो भारत ने अधिक रफ्तार से प्रगति की होती। उन्होंने कहा, फजमीन पर जो कब्जा है वही अपना है, बाकी तो सब अदालत और कचहरी का काम है। उससे फर्क नहीं पड़ता। 21वें अलंकरण समारोह में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की ओर से आयोजित रूस्तमजी मेमोरियल लेक्चर में शुक्रवार को एनएसए डोभाल ने कहा कि भारत की आर्थिक प्रगति अधिक रफ्तार पकड़ती अगर देश की सीमाएं अति



नई दिल्ली, एजेसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में बैठे आम आदमी पार्टी (आप) के शीर्ष नेता रिमोट कंट्रोल के जरिए पंजाब सरकार को नियंत्रित कर रहे हैं और कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री अपने दम पर कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। गुरदासपुर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुर्भाग्य से पंजाब को रिमोट कंट्रोल के माध्यम से शासित किया जा रहा है। दिल्ली के दरबारी पंजाब पर शासन कर रहे हैं। पंजाब के सीएम अपने दम पर एक भी निर्णय नहीं ले सकते। अपनी सरकार चलाने के लिए नए आदेश लेने के

आपका रुपया कब्रिस्तान में नहीं, देश के विकास में खर्च हो रहा - सीएम योगी

देवरिया, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा सुरक्षा है, सम्मान है, विकास है, गरीबों का कल्याण है, विरासत है, आस्था का सम्मान है। एक तरफ जहां बीजेपी पीएम मोदी के नेतृत्व में हर काम कर रही है। क्या हमने जाति के आधार पर कुछ किया है? योगी ने कहा कि एक ही मंत्र है सबका साथ, सबका विकास। विपक्ष पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। ये बड़ा ही अनर्थकारी है। जब भी उनका गठबंधन बनता है तो आतंकी हमले होते हैं। योगी ने कहा कि प्रदेश में सपा और केंद्र में कांग्रेस के शासन में अयोध्या के रामलला मंदिर और

राष्ट्रीय हितों और देश की सुरक्षा का ध्यान रखना होता है। देश की सीमाएं अत्यधिक महत्वपूर्ण इसलिए हैं, क्योंकि वह हमारी संप्रभुता को

परिभाषित करती हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दस सालों में भारत सरकार ने सीमाओं की सुरक्षा पर बहुत ध्यान दिया है। इसी अवधि



काम आतंकावादियों के खिलाफ कामते वापस लेने का किया, सौम्याय से अदालत ने हस्तक्षेप किया। वही महाराजगंज में एक सभा में योगी ने कहा कि अब आपका रुपया कब्रिस्तान में नहीं देश के विकास

कब्रिस्तान में लगा देते थे। पहले की सरकारों में चार लोग टोपी पहन कर गरीबों की भूमि कब्जा कर लेते थे। अब ऐसा संभव नहीं है। धर्म के आधार पर आस्था नहीं का हकदार नहीं हो सकता है।

संपादकीय

जल–संकट चुनाव जीतने का नहीं

देश के कई भागों में भीषण गर्मी पड़ रही है, जैसे–जैसे गर्मी प्रचंड होती जा रही है, जल संकट की खबरें भी डराने लगी है। राजस्थान, दिल्ली, कर्नाटक आदि प्रांतों में पानी के लिये त्राहि–त्राहि मची है। मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले महर–खुवा गांव में जल–संकट की तस्वीरें भयावह एवं डराने वाली है। इस गांव में लगभग 100 आदिवासी परिवार रहते हैं, जिनके पास अब इतना भी पानी नहीं बचा है कि ये दिन में दो वक्त का खाना बना सकें और अपनी प्यास बुझा सकें। ऐसे हजारों गांव हैं, जहां पानी के अभाव में जीवन संकट में हैं। भारत अपने इतिहास के सबसे गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। लोकसभा चुनाव अन्तिम चरण की ओर अग्रसर है, आज हमारे उम्मीदवार मुप्त बिजली और पानी देने का वादा करके चुनाव तो जीत जाते हैं लेकिन भारत में जिस तरह पानी का संकट गंभीर हो रहा है, उससे उनकी कथनी और करनी की असमानता ही बार–बार उजागर होती है। जल–संकट चरम पराकाष्ठा पर है, एक दिन ऐसा भी आ सकता है, जब पैसा देकर भी पानी खरीदना मुश्किल हो जाएगा। जल–संकट चुनाव जीतने एवं राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा तो है, लेकिन समाधान का नहीं। जल संकट ने राजनीतिक रंग तो ले लिया है, विभिन्न राजनीतिक दल एक–दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं और पिस रहा आम आदमी। पैसे वालों के लिए पानी इतनी बड़ी समस्या नहीं है लेकिन जिन लोगों के पास पैसों की किल्लत है, वे पानी की किल्लत से भी जूझ रहे हैं क्योंकि टैंकर का पानी महंगा पड़ रहा है। वास्तव में लगातार बढ़ती गर्मी के कारण जल स्तर में तेजी से गिरावट आ रही है। इसके गंभीर परिणामों के चलते राजस्थान, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में पानी की कमी ने गंभीर रूप धारण कर लिया है। देश का आईटी हब बेंगलुरु गंभीर जल संकट से दो–चार है। जिसका असर न केवल कृषि गतिविधियों पर पड़ रहा है बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। केंद्रीय जल आयोग के नवीनतम आंकड़े भारत में बढ़ते जल संकट की गंभीरता को ही दर्शाते हैं। आंकड़े देश भर के जलाशयों के स्तर में आई चिंताजनक गिरावट की तस्वीर उकेरते हैं। देश में प्रमुख जलाशयों में उपलब्ध पानी में उनकी भंडारण क्षमता के अनुपात में तीस प्रतिशत की गिरावट आई है। जो हाल के वर्षों की तुलना में बड़ी गिरावट है। जो सूखे जैसी स्थिति की ओर इशारा करती है। महर–खुवा गांव की ही तरह अलवर जिले के कई गांव में लोग किसी एक मौसम में नहीं, बल्कि 12 महीनें भीषण जल संकट का सामना कर रहे हैं। इन गांवों में पानी का स्रोत है ही नहीं। इन इलाकों में पानी की इतनी कमी है कि लोग उसे अपने घरों में टैंकर में छिपाकर और ताला लगाकर सुरक्षित रखने लगे हैं। भारत के गांवों में रहनेवाले करीब 20 करोड़ परिवारों के घरों में नल नहीं है। इन परिवारों की ओरतें पैदल चलकर, घंटों लाइन में लगरकर पानी इकट्ठा करती हैं। इसी चुनौती से निपटने के लिए मोदी सरकार ने साल 2019 में हर घर में नल से पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन की घोषणा की। सरकार का दावा है कि अब तक 10 करोड़ घरों में नल लग गए हैं। लेकिन अभी हजारों गांवों में जल–संकट एक बड़ी समस्या बनी हुई है। एक नागरिक के रूप में हम आत्ममंथन करें कि बढ़ते जल–संकट के समाधान की दिशा में हमने क्या कदम उठाये। क्या पानी की फिजूल खर्ची को कम करने का कोई संकल्प लिया? गर्मी के आने पर हम हाय–हाय तो करने लगते हैं, लेकिन कभी हमने विचार किया कि हम इस स्थिति को दूर करने के लिये क्या योगदान देते हैं? क्या हम पौधा–रोपण की ईमानदार कोशिश करते हैं? हम जल के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास करते हैं? क्या वर्षा जल सहेजने का प्रयास करते हैं ताकि तापमान कम करने व भूगर्भीय जल के संरक्षण में मदद मिले? सच कहें तो हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के अनुरूप जैसी जीवन शैली विकसित की थी, वह हमें कुदरत के चरम से बचाती थी। राजस्थान में जल–संकट की संभावनाओं को देखते हुए आम नागरिक खुद के स्तर पर व्यापक प्रयत्न करता है। रेगिस्तान से जुड़े अनेक गांवों एवं शहरों में बने या बनने वाले मकानों में कुआ जरूर होता है, जहां बरसात के पानी को एकत्र किया जाता है, जो संकट के समय काम आता है। इसलिये गाँव के स्तर पर लोगों के द्वारा बरसात के पानी को इकट्ठा करने की शुरुआत करनी चाहिये। उचित रख–रखाव के साथ छोटे या बड़े तालाबों को बनाने के द्वारा बरसात के पानी को बचाया जा सकता है। हम महसूस करें कि बढ़ती जनसंख्या का संसाधनों में बढ़ता दबाव भी तापमान की वृद्धि एवं जल–संकट का कारण है। बड़ी विकास परियोजनाओं व खनन के लिये जिस तरह जंगलों को उजाड़ा गया, उसका खमियाजा हमें और आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। विलासिता के साधनों, वातानुकूलन के मोह, वाटर–पाफ़ो एवं होटलों में पानी के अव्यय को रोकने के लिये जन–चेतना जागृत करने की अपेक्षा है। हमारे पुरखों ने मौसम अनुकूल खानपान, परंपरागत पेय–पदार्थों के सेवन तथा मौसम अनुकूल जीवन शैली के साथ–साथ जल–संरक्षण का ऐसा ज्ञान दिया, जो हमें मौसम के चरम में सुरक्षित रख सकता है। एक व्यक्ति के रूप में हम बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे जल–संकट से खुद व समाज को सुरक्षित कर सकते हैं। सरकार व समाज मिलकर जल–संकट का मुकाबला कर सकते हैं। भारत में जल–संकट की समस्या से निपटने के लिये प्राचीन समय से जो प्रयत्न किये गये है, वे दुनिया के लिये मार्गदर्शक हैं।

घरेलू स्तर पर फिलिस्तीन और मुस्लिम मुद्दे पर भारत का रुव

विनोद भारत को यह सुनिश्चित करने में सावधानी बरतनी चाहिए कि फिलिस्तीन पर उसके रुख को



मुसलमानों से जुड़े घरेलू राजनीतिक विवाद के विस्तार के रूप में नहीं आया। अतीत में, इजरायलियों ने पश्चिम एशिया की इस्लामी शक्तियों के प्रति भारत के प्रेमालाप

अरुण जलवायु परिवर्तन का वैश्विक संकट गंभीर होता जा रहा है. वैज्ञानिक तापमान वृद्धि रोकने के लिए कार्बन उत्सर्जन घटाने पर अड़े हुए हैं. समस्या बढ़ने की तुलना में समाधान की गति धीमी है क्योंकि आधुनिक जलवायु विज्ञान एक अपूर्ण विज्ञान है. भौतिक एवं रासायनिक प्रणाली पर वैज्ञानिकों का अत्यधि क ध्यान है, जिसमें वे ऊर्जा एवं तत्वों के संचरण को बेहतर करना चाहते हैं. इसके साथ–साथ आर्थिक एवं राजनीतिक तंत्र में भी बदलाव आवश्यक है ताकि धन एवं शक्ति का संचरण बेहतर हो सके. पिछली सदी में उत्पादकता, विकास और जीवन स्तर में बेहतरी ऊर्जा के कार्बन एवं हाइड्रोकार्बन स्रोतों पर लगातार निर्भर होती गयी. इसलिए अन्य ऊर्जा स्रोतों को खोजना और हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल कम करने के उपाय करना बहुत जरूरी है. उत्सर्जन घटाने के लिए जीवनशैली और उत्पादन तंत्रों में बदलाव और दरकार है. साथ ही, सौर ऊर्जा जैसे नवीनीकृत स्रोतों को अपनाया

किसानों को खेती से जोड़े रखना एक गंभीर चुनौती

भारत एक कृषि प्रधान देश है लेकिन देश में कृषि की तुलना में उद्योग और सेवा आदि क्षेत्रों का तेजी से विस्तार होने के कारण इस मौलिक व्यवसाय का योगदान जीडीपी में जिस तेजी से घट रहा है। कृषि कर्म में लगे लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवासन के कारण किसानों को खेती में प्रवृत्त रखना एक गंभीर चुनौती ही है। यह दोधारी चुनौती एक बड़ी आबादी को आजीविका के अवसर प्रदान करने के साथ ही जनसंख्या की आवश्यकतानुसार देश का अन्न उत्पादन बनाए रखने की भी है। हर रोज किसानों की आत्महत्याओं की समाख्या भी इसी चुनौती से जुड़ी हुई है।

हर साल होता है करोड़ों किसानों का प्रवासन

खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के एक आकलन के अनुसार भूख, गरीबी और जलवायु

परिवर्तन के कारण होने वाले मौसमी बदलाव की वजह से लगभग 76.3 करोड़ लोग अपने ही देश में किसानी छोड़कर बेहतर आजीविका अवसरों

ममता सरकार सवैधानिक व्यवस्था से अग्र से नहीं

योगेंद्र पश्चिमी बंगाल की ममता सरकार देश में एकमात्र ऐसी सत्तारूढ़ पार्टी बन गई है जिसका देश के संविधान और न्यायपालिका में भरोसा नहीं रह गया है। भ्रष्टाचार से लेकर मनमर्जी का शासन चलाना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का शगल बन गया है। ममता को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति नजर आती है, इसके लिए देशक कानून की कितनी ही ध्ज्जियां क्यों न उड़ानी पड़ी। ममता बनर्जी का एकमात्र लक्ष्य मुसलमानों के वोट बैंक को बरकरार रखना रह गया है। मुद्दा चाहे रेहिंग्या मुसलमानों के अवैध प्रवेश का हो या फिर बांग्ला देशियों का। इसके लिए ममता

ने देश की एकता–अखंडता और सुरक्षा से जुड़े इन मुद्दों पर भी केंद्र की भाजपा सरकार की खिलाफत की है। कानून से खिलवाड़ जितना और न्यायपालिका में भरोसा नहीं रह गया है। कांग्रेस के शक्ति राख्यों ने हुआ है उतना शायद ही देश के किसी दूसरे राख्यों में हुआ हो। कांग्रेस शासित राख्यों के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के हाइकमान ने भी कभी ऐसे आरोप केंद्र की भाजपा सरकार पर नहीं लगाए, जैसे कि ममता बनर्जी लगाती रही हैं। ममता ने भ्रष्टाचार, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग, राजनीतिक आधार पर बंदखाट जैसे मुद्दों पर अदालतों से जितनी फटकार खाई है, उतनी देश के किसी राजनीतिक दल की सरकार ने नहीं खाई। इतना

संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद 4 के अनुसार, और इसलिए, इसे स्वीकार किया जाना चाहिए खारिज कर दिया गया रिपब्लिकन जॉन बोल्टन, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व राजदूत और साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैसे अमेरिकी बाजों का दावा है कि फिलिस्तीन एक राज्य नहीं है क्योंकि इसकी न तो औपचारिक सीमाएँ हैं और न ही संप्रभु अधिकार। सुश्री कंबोज ने दक्षिण कैरोलिना के रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम के जानलेवा दृष्टिकोण को भी साझा नहीं किया है, जिन्होंने एनबीसी से साक्षात्कार में सुझाव दिया था कि गाजा, जहां इजरायली बमबारी ने पहले ही लगभग 35,000 फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया गुटेरेश के दृष्टिकोण का उनका समर्थन, कि षफिलिस्तीन राज्य संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता के लिए योग्य है,

वातावरण पर गरीबों की तुलना में धनी लोग कहीं अधिक दबाव बनाते हैं, जबकि सबके लिए उपलब्ध संसाधनों में सबकी न्यायपूर्ण साझेदारी होनी चाहिए. बैंकों एवं वित्तीय सेवाओं समेत सभी उद्योगों के उत्तरोत्तर निजीकरण के कारण अधिक पैसे वाले लोग सार्वजनिक नीतियों को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं. जलवायु परिवर्तन के मामले में तकनीक के चयन की शक्ति ६ ानी निवेशकों के हाथ में है, जो इस समस्या से सबसे कम प्रभावित हैं तथा उनकी मुख्य चिंता निवेश की कमाई से जुड़ी होती है. इस तरह संपत्ति का प्रवाह शीर्ष की ओर बना रहता है. धनी और धनी हो रहे हैं, आर्थिक विषमता बढ़ती जा रही है. इससे जलवायु परिवर्तन का समुचित समाधान खोजने में और भी देरी हो रही है. कार्बन कटौती पर केंद्रित वैज्ञानिक समझ संकीर्ण है, इसका विस्तार किया जाना चाहिए. पहला विस्तार तबचें एवं ऊर्जा के संबंध में होना चाहिए. इस जलवायु मॉडल में पृथ्वी पर विभिन्न रूपों में प्रवाहित हो रहे

हैं, लेकिन कृषिकर्म से जुड़े लोगों के लिए प्रवासन एक मजबूरी है जो कि बढ़ती जा रही है। अर्थात् कृषि भूमि, विकास की कमी और खराब पारिवारिक अर्थव्यवस्था के कारण मजदूरों को अपना क्षेत्र छोड़ने की प्रवास करते हैं और लगभग 2 प्रतिशत लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं। पूर्वी और उत्तर–पूर्वी क्षेत्रों से बड़ी तादाद में लोग काम और बेहतर रोजगार की तलाश में भारत के विभिन्न हिस्सों में चले जाते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग अल्पकालीन प्रवासी हैं जो थोड़े समय के लिए मजदूरी करते हैं और इसके बाद अपने मूल राज्य में लौट कर अपनी छोटी जेतों पर काम करते हैं। एनसीआरबी द्वारा दिसंबर 2023 में जारी क्राइम स्टेटिटिस्टिक्स के अनुसार वर्ष 2022 में देश में 11,290 किसानों ने आत्महत्या की जिनमें 6083 कृषि मजदूर थे। अर्थव्यवस्था में 15 प्रतिशत रह गई कृषि की हिस्सेदारी प्रवासन दुनियाभर में कई गरीब लोगों के लिए जीवन जीने का एक तरीका है और सहस्राब्दियों से रहा

सब कुछ होने के बावजूद ममता बनर्जी अपनी आदतों से बाज नहीं आई हैं। नया मामला पश्चिमी बंगाल में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को अदालत द्वारा रद्द करने का है। इस आदेश को सदाशयता से मान कर अपील करने की दलील देने के बजाए मुख्यमंत्री ममता ने ही फैसला देने वाले हाईकोर्ट के न्यायाध

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तुणमूल कांग्रेस प्रशासन के तहत 2011 से बंगाल में जारी अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी प्रमाणपत्रों को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया। अदालत ने कहा, हालांकि, इससे वर्तमान में शैक्षणिक संस्थानों में नौकरी या सीटें रखने वाले या जाति प्रमाण पत्र के साथ आवेदन दाखिल करने वाले लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण की पूरी कमानों में नौकरी या सीटें रखने के कार्यकाल में गठित सच्वर कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित है। उस रिपोर्ट में देश में मुस्लिम समुदाय की स्थिति के बारे में विस्तृत बातें दी गई थीं। रिपोर्ट में कहा गया था

इसके चार्टर के अनुच्छेद 4 के अनुसार, और इसलिए, इसे स्वीकार किया जाना चाहिए खारिज कर दिया गया रिपब्लिकन जॉन बोल्टन, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व राजदूत और साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैसे अमेरिकी बाजों का दावा है कि फिलिस्तीन एक राज्य नहीं है क्योंकि इसकी न तो औपचारिक सीमाएँ हैं और न ही संप्रभु अधिकार। सुश्री कंबोज ने दक्षिण कैरोलिना के रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम के जानलेवा दृष्टिकोण को भी साझा नहीं किया है, जिन्होंने एनबीसी से साक्षात्कार में सुझाव दिया था कि गाजा, जहां इजरायली बमबारी ने पहले ही लगभग 35,000 फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया गुटेरेश के दृष्टिकोण का उनका समर्थन, कि षफिलिस्तीन राज्य संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता के लिए योग्य है,

संयुक्त राष्ट्र के उस कदम पर इजराइल की उन्मादी प्रतिक्रिया, जिसे बिडेन प्रशासन के वीटो ने निरस्त कर दिया, ने चेतावनी दी कि कोई भी समाधान तब तक संभव नहीं है जब तक कि दृष्टिकोण मौलिक रूप से नहीं बदलता है और दोनों पक्षों के उद्देश्यों की कुछ समझ नहीं होती है। जबकि फिलिस्तीनियों को अमेरिका और दुनिया को यह विश्वास दिलाना होगा कि हमास की 7 अक्टूबर की हत्या की घटना फिर कभी नहीं दोहराई जाएगी, और वे उस इजराइल के साथ शांति से सह–अस्तित्व के लिए तैयार हैं जिसे कई अमेरिकी विदेश में अपने सबसे विश्वसनीय सहयोगी के रूप में देखते हैं, जिनमें से 70 प्रतिशत शिशु, महिलाएं और बच्चे थे। परमाणु बम से हमला करना चाहिए, लेकिन

है. कथित वैज्ञानिक तरीके से पानी के भंडारण और बहाव के प्रबंधन

के लिए बड़े–बड़े बांध बना दिये गये हैं. पर्यावरण पर इनका गंभीर असर पड़ा है. जब प्राकृतिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह मानव–निर्मित इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया जाता है, तब जीडीपी बढ़ जाती है. लेकिन जीवन के बने रहने की स्थिति कमतर हो जाती है. तीसरी बात यह है कि इस्पात के इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रकृति के जलीय इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया गया है. पहाड़ियों को समतल बना दिया गया है तथा सड़क बनाने एवं शहर बसाने के लिए जलाशयों को पाट दिया गया

है. कथित वैज्ञानिक तरीके से पानी के भंडारण और बहाव के प्रबंधन के लिए बड़े–बड़े बांध बना दिये गये हैं. पर्यावरण पर इनका गंभीर असर पड़ा है. जब प्राकृतिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह मानव–निर्मित इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया जाता है, तब जीडीपी बढ़ जाती है. लेकिन जीवन के बने रहने की स्थिति कमतर हो जाती है. तीसरी बात यह है कि इस्पात के इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रकृति के जलीय इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया गया है. पहाड़ियों को समतल बना दिया गया है तथा सड़क बनाने एवं शहर बसाने के लिए जलाशयों को पाट दिया गया

महाशक्ति है। यह दूध, दालों और मसालों का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसमें दुनिया का सबसे बड़ा मवेशी झुंड है। यह चावल, गेहूँ, कपास, गन्ना, मछली, भेड़ और बकरी का मांस, फल, सब्जियां और चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में लगभग 19.5 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है, जिसमें से लगभग 63 प्रतिशत वर्षा आधारित है, जबकि 37 प्रतिशत सिंचित है।

चुनौतियां ही चुनौतियां हैं कृषि क्षेत्र के समक्ष कृषक समुदाय के समक्ष पारंपरिक पेशे से जुड़े रहने में एक नहीं बल्कि अनेकों चुनौतियां हैं। कई किसान बाजार की कीमतों में उतार–चढ़ाव, मौसम की अनिश्चितता और बढ़ती इनपुट लागत जैसे विभिन्न कारकों के कारण कम और अस्थिर आय से जूझते हैं। यह आर्थिक अस्थिरता उनके लिए केवल कृषि के माध्यम से अपना गुजारा करना कठिन बना देती है। पारंपरिक कृषि पद्धतियों में अक्सर आधुनिक कृषि पद्धतियों की तुलना में दक्षता और उत्पादकता

की कमी होती है। आधुनिक उपकरणों, मशीनरी और प्रौद्योगिकियों तक सीमित पहुंच उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बाधित करती है, जिससे युवा पीढ़ी कृषि पेशे में प्रवेश करने या जारी रखने से हतोत्साहित हो रही है। विरासत बड़ा उत्पादक है। देश में लगभग 19.5 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है, जिसमें से लगभग 63 प्रतिशत वर्षा आधारित है, जबकि 37 प्रतिशत सिंचित है। चुनौतियां ही चुनौतियां हैं कृषि क्षेत्र के समक्ष कृषक समुदाय के समक्ष पारंपरिक पेशे से जुड़े रहने में एक नहीं बल्कि अनेकों चुनौतियां हैं। कई किसान बाजार की कीमतों में उतार–चढ़ाव, मौसम की अनिश्चितता और बढ़ती इनपुट लागत जैसे विभिन्न कारकों के कारण कम और अस्थिर आय से जूझते हैं। यह आर्थिक अस्थिरता उनके लिए केवल कृषि के माध्यम से अपना गुजारा करना कठिन बना देती है। पारंपरिक कृषि पद्धतियों में अक्सर आधुनिक कृषि पद्धतियों की तुलना में दक्षता और उत्पादकता

कि पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों में केवल 3.5 फीसदी ही मुस्लिम थे। इसी को आधार बनाकर मोर्चा सरकार ने 53 जातियों को ओबीसी की श्रेणी में डाल दिया और ओबीसी आरक्षण सात फीसदी से बढ़ाकर 17 फीसदी कर दिया। इस तरह उस वक्त करीब 87.1 फीसदी मुस्लिम आबादी आरक्षण के दायरे में आ गई। लेकिन, 2011 में वाम मोर्चा की सरकार सत्ता से बाहर हो गई और उसका यह फैसला कानून नहीं बन सका। फिर राज्य में तुणमूल कांग्रेस की सरकार आई और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनीं। ममता की सरकार ने इस सूची को बढ़ाकर 77

कर दिया। 35 नई जातियों को इस सूची में जोड़ा गया, जिसमें से 33 मुस्लिम समुदाय की जातियां थीं। साथ ही तुणमूल सरकार ने भी राज्य में ओबीसी आरक्षण सात फीसदी से बढ़ाकर 17 फीसदी कर दिया। ममता सरकार के इस कानून की वजह से राज्य की 92 फीसदी मुस्लिम आबादी को आरक्षण का लाभ मिलने लगा। हाईकोर्ट ने ओबीसी के मामले में सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया। इसके बाद तो मानो ममता का पारा उछल गया। ममता ने अदालत पर मनमाने आरोप लगा दिए। उच्च न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीशों पर निशाना साधते हुए एक न्यायाधीश कर रहा है।

है, या कोई ताजा उकसावा था? यह भी पढ़ें– आकार पटेल संयुक्त राष्ट्र से संबंध खत्म होने के बाद, भारत मानवाधिकार निकाय में दोषी सारात है। इजराइल को इसी तरह फिलिस्तीनियों और दुनिया को एक संभ्रमु फिलिस्तीन के बगल में शांति से रहने की इच्छा के बारे में आश्चर्य करना होगा। इसमें चार मील नेटजारिम कॉरिडोर या रूट 749 के उद्देश्य को समझाना शामिल है, जिसे इजरायली सेना ने पूर्व से पश्चिम तक, गाजा–इजरायल सीमा से भूमू-ए सागर तक छोदा है। कई लोग सोचते हैं कि गलियारों का उद्देश्य पूरे गाजा पट्टी में दूरदराज के आवासीय बस्तियों में भी इजरायली रक्षा बलों द्वारा स्थायी सैन्य निगरानी सुनिश्चित करना और उत्तरी और मध्य गाजा में इजरायली छापे की सुविधा प्रदान करना है। भारत के मुस्लिम

